क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 126, शनिवार, 01 जून, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सकीं मेनका गांधी बन सकती हैं लोकसभा की अस्थायी अध्यक्ष

नई दिल्ली। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 17वीं लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) बन सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि आठ बार की सांसद मेनका को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बार वह उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई हैं। मेनका इससे पहले की मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थीं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसी के तहत ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होता है। 17वीं लोकसभा के विजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुल संख्या 78 है। महिला सांसदों की अब तक की इस सर्वाधिक भागीदारी के साथ ही नई लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो जाएगी। महिला सांसदों की सबसे कम संख्या नौवीं लोकसभा में 28 थी। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा की 542 सीटों के लिये शुक्रवार को घोषित पूर्ण परिणाम के आधार पर सर्वाधिक 40 महिला उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने महिला उम्मीदवार के रूप में रायबरेली से जीत दर्ज की है। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मोदी सरकार की केन्द्रीय मंत्रियों में अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने वालों में मेनका गांधी सुल्तानपुर से और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 'अपना दल' उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती हैं। साथ ही भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी मथुरा से, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से, किरण खेर चंडीगढ़ से और रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से जीतने वाली प्रमुख भाजपा सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 724 महिला उम्मीदवार थीं।

मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा

अमित शाह गृह मंत्री तो राजनाथ सिंह बने रक्षा मंत्री

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में अमित शाह को गृह मंत्रालय और राजनाथ को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, परमाणु ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण नीति से जुड़े मुद्दों वाले तथा बिना आवंटित विभाग रहेंगे। पूर्व विदेश सचिव रहे एस जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्रालय मिला । पीयूष गोयल फिर से रेल मंत्री बनाये गए हैं। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है जबकि प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण

तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने रहेंगे । धर्मेन्द्र प्रधान के पास पेट्रोलियम मंत्रालय बना रहेगा। राम विलास पासवान उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने रहेंगे । नरेन्द्र सिंह तोमर नये कृषि मंत्री होंगे, उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी रहेगा। रविशंकर प्रसाद दूरसंचार के अलावा विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे जबकि रमेश पोखरियाल निशंक नये मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 24 कैबिनेट मंत्रियों, नौ ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। दरअसल, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गुरुवार को उनके अलावा 24 कैबिनेट मंत्रियों, नौ राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार के सहित 57 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिपरिषद में राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद में सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभु, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, महेश शर्मा, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, सत्यपाल सिंह, के जे एलफोंस को नयी सरकार में स्थान नहीं मिला है । नई सरकार में उमा भारती और मनोज सिन्हा भी शामिल नहीं हैं। सुषमा और उमा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जबकि मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। अनंत गीते और हंसराज अहीर चुनाव हार गए और वे भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हैं।

मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुषमा स्वराज ने कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली।

पीएम मोदी की दूसरी सरकार का हिस्सा नहीं सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। बता दें सुषमा स्वराज को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर दिन भर अटकलों का दौर चलता रहा लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उनके मेहमानों के साथ दर्शक दीर्घा में बैठने के साथ ही इन अटकलों को विराम लग गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधान मंत्री जी - आपने 5 वर्षों तक मुझे विदेश मंत्री के तौर पर देशवासियों और प्रवासी भारतीयों की सेवा करने का मौका दिया और पूरे कार्यकाल में व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सम्मान दिया। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। हमारी सरकार बहुत यशस्विता से चले, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुषमा स्वराज को भले ही मंत्री नहीं बनाया गया हो, लेकिन उनके अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सोशल मीडिया के जरिए उनसे आसानी से संपर्क साधा जा सकता था। वह विदेशों में मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए काफी मशहूर हुईं। सुषमा हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुषमा, मेनका गांधी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है जबकि

पिछली सरकार में वह प्रमुख मंत्री माने जाते थे। सुषमा ने स्वास्थ्य कारणों से इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। अपने पिछले कार्यकाल में वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहीं और विदेशों में बसे भारतीयों से बड़े पैमाने पर संवाद किया। विदेशों में बसे भारतीय अगर किसी मुश्किल में होते तो अपने संकटमोचक के तौर पर वह तुरंत सुषमा को याद करते। पूर्व विदेश मंत्री ने भी शायद ही उन्हें कभी निराश किया हो। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा ने पासपोर्ट संबंधी आधारभूत संरचना का विस्तार किया और पूर्वी देशों के साथ संवाद बढ़ाया। सुषमा को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही विदेश मंत्री बनाया गया था। वह दिवंगत इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली दूसरी महिला रही हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था। सुषमा ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर दी थी।

बताएं नीरव मोदी को किस जेल में रखेंगे? ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय अधिकारियों से पूछा

नई दिल्ली।

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी 30 मई को चौथी बार ब्रिटेन की अदालत में पेश हुआ। एकबार फिर से उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और न्यायिक हिरासत 27 जून तक बढ़ा दी गई है। 27 जून को ही मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि वह 14 दिनों में बताए कि उसे किस जेल में रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान जज एम्मा आर्बुथनोट ने कहा कि आखिरकार 14 दिनों के भीतर भारत सरकार जेल के बारे में क्यों नहीं खुलासा कर सकती है। साथ में उन्होंने मुंबई स्थिर आर्थर रोड जेल का नाम भी लिया। बता दें, नीरव मोदी से पहले विजय माल्या के मामले में भी जज एम्मा आर्बुथनोट ने ही उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी ती थी।

दिसंबर 2018 में उन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर फैसला सुनाया था, उससे पहले भारतीय जांच एजेंसियों ने आर्थर रोड जेल की उस सेल का वीडियो दिखाया था जहां माल्या को रखा जाएगा। अब जब नीरव मोदी मामले की सुनवाई हो रही है तो जज ने कहा कि अगर मोदी को भी उसी तरह की सेल में रखा जाता है तो कोर्ट को इसमें कोई परेशानी नहीं है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कर्ज में 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में भारतीय कानून के हवाले किए जाने की भारतीय एजेंसियों की अर्जी को ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दे रहा है। फिलहाल, वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। मोदी को लंदन पुलिस ने प्रत्यर्पण वारंट पर लंदन के मेट्रो बैंक से गिरफ्तार किया था। वह उस समय 19 मार्च को एक नया बैंक खाता खोलने का प्रयास कर रहा था। तब से वह जेल में है।

अमरिंदर के हमले पर सिद्धू बोले, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं

चंडीगढ़।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू पर डालने वाले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूर्व क्रिकेटर ने करारा जवाब दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेने की बजाय 50 विभागों में से केवल मेरे विभाग से सवाल पूछा गया क्यों? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी वैसा करूंगा। मैं पहले कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पहले कुछ नहीं कहा था, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। वह (पंजाब सीएम) कोई भी फैसला ले सकते हैं, मैं उसका पालन करूंगा।

सिद्धू ने कहा, शिकायत करना मेरी फितरत नहीं हैं, मैंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के खिलाफ कभी बोला है? मैं अपने किसी भी स्टैंड पर एक इंच भी पीछे हुआ क्या? जो पहले कहता रहा हूं, वो कहता रहूंगा। पार्टी का विषय है, सिद्धू ने अपने स्थानीय निकाय विभाग के कामकाज का भी बचाव करते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार के किसी और मंत्री ने इतनी पारदर्शिता से काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने हाल में कहा था कि मंत्री के तौर पर सिद्धू के प्रदर्शन की समीक्षा की जरूरत है और वह अपना ही विभाग संभाल पाने में सक्षम नहीं हैं, इसके बाद सिद्धू की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सिद्धू शहरी विकास मंत्री हैं। बेअदबी मामले में सिद्धू की टिप्पणी का बठिंडा में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ने की संभावना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद वह पार्टी आलाकमान के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए सिद्धू ने कहा कि जब उन्होंने विभाग का जिम्मा संभाला था तो वह दिशाहीन जहाज था। क्रिकेटर से अभिनेता बने सिद्धू ने कहा कि बीते दो साल में उनके विभाग ने 6000 करोड़ रुपये अर्जित किये। उसकी सभी परियोजनाएं युद्धस्तर पर पूरी की जा रही हैं। सिद्धू ने कहा, वही आठ या नौ लोग हैं जो पूर्व में भी उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला।

मायावती ने 3 जून को दिल्ली में बुलाई बसपा की बैठक

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक करने जा रही हैं। वह 3 जून को दिल्ली में बैठक करेंगी। इसमें नवनिर्वाचित सांसद, लोकसभा प्रत्याशी, जोन इंचार्जों के साथ जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मायावती की यह बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। बसपा प्रमुख लोकसभा चुनाव में गठबंधन को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों की जहां समीक्षा करेंगी, वहीं भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा करेंगी। बसपा के जिलाध्यक्षों, जोन इंचार्जों, नवनिर्वाचित सांसदों व लोकसभा प्रत्याशियों को 3 जून को दिल्ली स्थिति केंद्रीय पार्टी कार्यालय 11 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर 10 बजे तक पहुंचने को कहा गया है। बसपा सुप्रीमो इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली सीटों और वोटिंग प्रतिशत की समीक्षा करेंगी। बसपा को लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिली हैं। उसका कुल वोटिंग प्रतिशत 19.26 रहा है। मायावती ने सीटवार ब्यौरा भी मांगा है। सूत्रों का कहना है कि मायावती इस दौरान पदाधिकारियों के साथ गठबंधन के भविष्य की संभावनाओं पर भी बातचीत कर सकती हैं। मायावती 23 मई को मतगणना वाले दिन ही रात में दिल्ली चली गई थीं। इन दिनों वह दिल्ली में ही हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव का रुझान आने के तुरंत बाद बातचीत में ईवीएम को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने गठबंधन को मिली सीटों पर चिंता जताते हुए कहा था कि अपेक्षा से कम सीटें मिली हैं। मायावती इसके बाद दिल्ली से ही पदाधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश दे रही थीं।

सारदा चिटफंड घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को दी गिरफ्तारी से राहत

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त निदेशक राजीव कुमार को 10 जुलाई तक गिरफ्तारी और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से गुरुवार को संरक्षण प्रदान किया। हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 10 जून से एक महीने के लिये उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और कुमार को आदेश दिये जाने के 24 घंटे के भीतर अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद 10 जून को अदालत खुलेगी। कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख को करोड़ों रुपये के चिटफंड मामले में सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा गया है। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि वह एक विशेष अधिकारी को प्रतिदिन शाम चार बजे कुमार के आवास उनकी हाजिरी दर्ज करने के लिये भेजे। न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता ग्रीष्मावकाश के बाद 12 जून को अदालत के दोबारा खुलने पर नियमित पीठ के समक्ष उपस्थित होगा। कुमार ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सीबीआई के उस नोटिस को रद्द करने की मांग की जिसमें सारदा चिटफंड घोटाला मामले में उन पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुमार को एक नोटिस भेजकर उनसे जांच में सहायता के लिये एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। कुमार के वकील सुदीप्तो मोइत्रा ने अदालत से कहा कि सीबीआई चिटफंड घोटाले के सिलसिले में बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किये उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने शिलॉन्ग में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी और अब बदले की भावना से उन्हें हिरासत में लेना चाहती है। सीबीआई के वकील वाईजे दस्तूर ने अदालत के समक्ष कहा कि कुमार एजेंसी द्वारा पूछे गए सवालों से बचते रहे हैं। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी नीत सरकार ने एडीजी, सीआईडी नियुक्त किया था।

टीम मोदी में शामिल न हो पाने वाले ये दो नेता संगठन को करेंगे मजबूत

नई दिल्ली। मंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए सांसद अब दिल्ली में संगठन को मजबूत करेंगे। हाईकमान ने दिल्ली के सांसदों को पहले ही निर्देश दे दिया था कि सभी विधानसभा की तैयारी में जुट जाएं। लोकसभा चुनावों के दौरान सक्रिय रहे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी इस बार कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए हैं। उन्हें भी संगठन मजबूत करने के काम में लगाया जाएगा। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मंत्री पद के दावेदार थे। मनोज तिवारी ने उत्तरी पूर्वी सीट पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को चुनाव में हराया है। वह दूसरी बार उत्तरी पूर्वीसीट से चुनाव

जीते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में बड़ा पूर्वांचल चेहरा हैं। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार मनोज तिवारी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन मनोज तिवारी को मंत्री नहीं बनाया गया।सूत्रों के मुताबिक, अभी पार्टी विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। ऐसे में मनोज तिवारी ने भी शपथ ग्रहण से पहले झुग्गी में रात बिताकर अपने इरादे जता दिए हैं। वह दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी की अटल सरकार और मोदी सरकार दोनों में मंत्री रहे विजय गोयल इस बार मंत्रियों की लिस्ट में नहीं हैं। वह राज्यसभा सांसद हैं। मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी विजय गोयल को बाद में शामिल किया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान विजय गोयल ने राजधानी में व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर अपनी ताकत दिखाई थी।

कानून मंत्री के लिए तीन तलाक बिल पास कराना चुनौती होगा

नई दिल्ली। मोदी सरकार में नए कानून मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के तीन तलाक बिल को पास कराने की। यह अभी अध्यादेश के रूप में लागू है। नई सरकार के कानून मंत्री के सामने 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' (देश में व्यावसाय करने की सरलता) की रेटिंग को बढ़ाने का जिम्मा भी होगा। गत वर्ष 2018 में भारत ने इस रैंकिंग को 23 अंक बढ़ाकर 77 पर आ गया था। 'ईज आफ डूइंग' बिजनेस न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में लगने वाला समय कम करने की रैंकिंग है। इसमें अनुबंध और सिविल वादों के निचली अदालतों में निपटारा शामिल है। मुकदमों में लगने वाला समय देश में कुछ कम हुआ है। यह समय अब 180 दिन के आसपास आ गया है। जबकि विकसित देशों में यह समय 90 दिन है। नए मंत्री के सामने इस समय को कम करने की चुनौती रहेगी। इसके अलावा उच्च न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में जजों की नियुक्तियों के लिए बनाए गए कानून एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की चुनौती भी सरकार के समक्ष रहेगी।

'जय श्री राम' के नारे को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर खोया अपना आपा

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपना आपा खो बैठी जब कुछ लोगों के एक समूह ने ''जय श्री राम'' के नारे लगाये। बनर्जी का काफिला उत्तरी 24 परगना जिले के संकटग्रस्त भाटपारा से गुजर रहा था तभी कुछ लोगों ने ''जय श्री राम'' के नारे लगाये जिसके बाद वह एक बार फिर अपना आपा खो बैठीं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुई

'हिंसा' के खिलाफ एक धरने में हिस्सा लेने के लिए नैहाटी जा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोग उस समय ''जय श्री राम'' के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जब बनर्जी का काफिला भाटपारा क्षेत्र से गुजर रहा था। इस क्षेत्र में चुनाव परिणामों की घोषणा होने के बाद से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा चल रही है।

यह क्षेत्र भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता है। सिंह ने

बनर्जी का काफिला उत्तरी 24 परगना जिले के संकटग्रस्त भाटपारा से गुजर रहा था तभी कुछ लोगों ने ''जय श्री राम'' के नारे लगाये जिसके बाद वह एक बार फिर अपना आपा खो बैठीं

चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी को पराजित किया है। क्रोधित बनर्जी अपने कार से बाहर आई और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों से इन पुरूषों के नाम लिखने को कहा। उन्हें यह कहते हुए सुना गया, ''आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप अन्य राज्यों से आएंगे, यहां रहें और हमारे साथ दुर्व्यवहार करें। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? आप सभी के नामों और विवरणों को लिख लिया जायेगा।'' मुख्यमंत्री के अपनी कार में वापस जाने के बाद उन लोगों ने फिर से ''जय श्री राम'' के नारे लगाये जिस वजह से उन्हें फिर से एक बार अपने वाहन से उतरना पड़ा। इसके बाद नैहाटी में धरने में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनकी कार के सामने आये और उन्हें अपशब्द कहने लगे। उन्होंने पूछा, ''क्या यहीं लोकतंत्र है?'' इस घटना ने इस महीने की शुरूआत में पश्चिमी मिदनापुर जिले के चन्द्रकोना के निकट हुई इसी तरह की एक घटना की याद दिला दी। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सामने आई एक वीडियो में बनर्जी उस समय अपना आपा खोती नजर आई थीं जब उनका काफिला क्षेत्र से गुजर रहा था तो कुछ लोग ''जय श्री राम'' के नारे लगा रहे थे।

संपादकीय

आर्थिक आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण देने के काम में एकाएक तेजी आ गई है। बुधवार को इसकी कई खबरें एक साथ आईं। सबसे पहले खबर आई कि दिल्ली सरकार ने आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार का यह आदेश पिछली तारीख से लागू किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक फरवरी के बाद से जितने खाली पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, उन सब पर यह लागू होगा। इस बीच एक अन्य खबर यह आई कि पंजाब सरकार ने दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अगले ही दिन एक तीसरी खबर भी आ गई कि गुजरात सरकार ने इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि से जुड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि जिन राज्यों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया, वे भी जल्द ही इस दिशा में बढ़ जाएंगे। दस फीसदी आर्थिक आरक्षण इसी साल जनवरी में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। तकरीबन सभी दल इस पर सहमत थे, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत तेजी से चली थी। जनवरी के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका फैसला किया था, अगले चंद रोज में ही संसद के दोनों सदनों ने इसके विधेयक को पास कर दिया था, और 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत भी कर दिए। गुजरात ने तभी इसे लागू करने की घोषणा कर दी थी, बाकी राज्य यह काम अब कर रहे हैं। हालांकि अभी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर कसा जाना शेष है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह आदेश दे चुका है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50 फीसदी से कम होना चाहिए। अभी यह देखना शेष है कि सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को दिए जाने वाले इस आरक्षण पर क्या रुख अपनाता है। इस आरक्षण से जुड़ी हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दस फीसदी आर्थिक आरक्षण के फैसले को चुनौती दी गई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आरक्षण का फैसला इस कोर्स पर लागू नहीं होता। अब नजर इस बात पर रहेंगी कि आगे कोर्ट क्या रुख अपनाता है? काफी समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जबकि यह उतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। कई कारणों से आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। जिन भी वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी गई है, उनकी सभी समस्याएं आरक्षण से नहीं सुलझी हैं। सशक्तीकरण में आरक्षण एक भूमिका भले ही निभा रहा हो, लेकिन व्यापक तौर पर देखें, तो लाभ पाने वाले वर्गों के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। वजह यह है कि इतनी सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं कि सभी को उसमें व्यवस्थित किया जा सके। बड़े पैमाने पर नौकरियां तेज औद्योगीकरण और निजी क्षेत्र के विस्तार से ही पैदा की जा सकती हैं। आरक्षण अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन सरकारों की प्राथमिकता इस समय तेज औद्योगीकरण होनी चाहिए। ऐसा हुआ, तो आरक्षण के लिए बनने वाले दबाव भी कुछ कम होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि औद्योगीकरण बढ़ाना अभी भी देश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

ट्वीट स्तर

बिहार के मिथिलांचल में जल स्तर का नीचे जाना और पानी की ऐतिहासिक कमी आज की तारीख में देश सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा होना चाहिए। यह ठीक ऐसा है जैसे चेरापूंजी में बारिश न हो।

नरेन्द्र नाथ, टिप्पणीकार

बिम्सटेक की सक्रियता से बेचैन पाकिस्तान

पुष्परंजन

नरेंद्र दामोदरदास मोदी के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में चीन से बचना था तो दक्षेस देशों के शासन प्रमुखों को बुलाने का रास्ता निकाला गया। इस बार उसी दक्षेस देशों के प्रमुख सदस्य पाकिस्तान को हाशिये पर डालना है तो 'बिम्सटेक' का तोड़ ढूंढा गया। पाकिस्तान का मीडिया और वहां का कूटनीतिक समुदाय इस बात को लेकर तपा हुआ है कि ट्विटर और फोन के ज़रिये डबल बधाइयां पाने के बावजूद पीएम मोदी ने इमरान खान को न्योता क्यों नहीं भेजा। पाक विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी की प्रतिक्रिया थी कि बिम्सटेक जैसे कम महत्व वाले संगठन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सोमवार शाम को कराची में जियो टीवी चैनल से बातचीत में पाक विदेशमंत्री ने कहा, 'पूरे चुनाव में पाकिस्तान को पानी पी-पीकर कोसा गया, फलस्वरूप मोदी सरकार अपार बहुमत से सत्ता में आई। बावजूद उसके, 22 मई को विश्केक में शंघाई कारापरेशन की बैठक में सुषमा स्वराज से मैं मिला। हमें नहीं आमंत्रित करने से सियाचिन, सर क्रीक और कश्मीर के नैरेटिव नहीं बदलने हैं। भारत को बातचीत के ज़रिये इसका हल निकालना ही होगा।' पाकिस्तान इस समय विसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। वह चाहकर भी बिम्सटेक के विरोध में बयान देने की स्थिति में नहीं है। पांच साल पहले शपथ ग्रहण के मौके पर सार्क देशों के शासन प्रमुखों को बुलाने के दो और मकसद थे। पहला, चीन को किनारे करके क्षेत्रीय सहयोग का वातावरण बनाना। दूसरा, पाकिस्तान-भारत के बीच विश्वास बहाली का माहौल तैयार करना। मगर, पीएम मोदी के शपथ के चंद महीने बाद काठमांडो में 26-27 नवंबर 2014 को 18वीं दक्षेस शिखर बैठक में जो परिदृश्य उपस्थित हुआ, उससे लगा नहीं कि सार्क की गाड़ी आगे खिसक पायेगी। काठमांडो बैठक मोदी और नवाज़ शरीफ के रूठने-मनाने तक केंद्रित रही। इस बात को मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि भारत-पाक अदावत का सीधा असर आठ सदस्यीय देशों के संगठन 'सार्क' पर पड़ा है। नतीजतन, इस्लामाबाद में 9-10 नवंबर 2016 को 19वीं सार्क समिट स्थगित करनी पड़ी। एक तरह से मानकर चलें कि पाक की अध्यक्षता वाली दक्षेस की दशा एक मृतप्राय घोड़े जैसी हो गई है। कोलंबो में सार्क की 20वीं शिखर बैठक इसी साल है। देखते हैं, वहां किस तरह का नया मोर्चा खुलता है। तो क्या शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्रीय संगठनों को आहूत करने का अभिनव प्रयोग विफल हो गया? बावजूद इसके, हम दोबारा से उसी राह पर क्यों चल पड़े? बिम्सटेक नेताओं को शपथ में बुलाने से चीन भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि बिम्सटेक के बजरिये 'वन बेल्ट वन रोड' (ओबीओआर) की महत्वाकांक्षा में मोदी रोड़े अटका रहे हैं। बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) में श्यांमार और थाईलैंड को हटा दें तो बाकी पांच सदस्य देश वही हैं जो दक्षेस में हैं। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान पांचों देश दक्षिण एशिया से हैं, शेष दो श्यांमार और थाईलैंड, पूर्वी एशिया से। भारत और भूटान को छोड़ दें तो बिम्सटेक के बाकी पांच सदस्य देश 'ओबीओआर' के समर्थक हैं और चीन के सामरिक-व्यापारिक लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण मुल्क है बांग्लादेश। इस समय चीन के लिए बांग्लादेश 16 अरब डॉलर वाले विशाल बाज़ार के रूप में दिखाई दे रहा है। चीन के मुकाबले मज़दूर वहां सस्ते हैं, इसलिए आउटसोर्स की संभावना उसे वहां अधिक दिख रही है। मलक्का जलडमरूमध्य वाले मार्ग पर निर्भरता को कम करने के वास्ते उसे बांग्लादेश के बरास्ते जहाज निकालना सस्ता व सुरक्षित लग रहा है। दक्षिण-पश्चिम चीन स्थित युन्नान के लिए बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस तरह से बलूचिस्तान का ग्वादर। चीन से यह दूरी एक हज़ार किलोमीटर की है। चीन को चिटगांव पोर्ट के माध्यम से ऊर्जा व्यापार बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। चिटगांव-ढाका के बीच बुलेट ट्रेन लाइन बैठाने पर भी काम चल रहा है। बांग्लादेश की तरह थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल की लगभग एक जैसी कहानी है। इन पांचों देशों में चीन ने अपने प्रभामंडल का विस्तार किया है। चीन ने एक नया इलाक़ा ढूंढा है, नाम है 'ब्लू इकोनॉमी।' इसमें निवेश करने वाले समुद्री इलाके में फिशरी का फायदा उठाने, मेरीटाइम टेक्नॉलोजी को आगे बढ़ाने, खनिज निकालने व गैस भंडार का दोहन करने में दिलचस्पी रखते हैं। चीन, बांग्लादेश के बजरिये बंगाल की खाड़ी में इस ब्लू इकोनॉमी को विस्तार देना चाहता है, यह बात बहुत जल्द सामने आने वाली है। 6 जून 1997 को बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बीआईएसटी-इसी) के नाम से इस संस्था की आधारशिला रखी गई। 1997 में म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान व नेपाल के सदस्य बन जाने के बाद, उसी साल 31 जुलाई को आहूत बैठक में इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन(बिम्सटेक) पड़ गया। बिम्सटेक व्यापार-निवेश, ट्रांसपोर्ट-कम्यूनिकेशन, ऊर्जा, पर्यटन, टेक्नॉलोजी, कृषि, मत्स्य पालन, जनस्वास्थ्य, ग़रीबी निवारण, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक सहयोग, नागरिकों के बीच संपर्क, आतंकवाद निरोध जैसे 14 लक्ष्यों को लेकर चल रहा था। दरअसल, इसे गतिशील करने का काम 4 मार्च 1914 को म्यांमार की राजधानी न्येपीदो की शिखर बैठक के बाद से आरंभ हुआ। मगर, उसके बाद के चार वर्षों में ऐसा कुछ उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ, जिसे लेकर 'बिम्सटेक' अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चर्चा का विषय बनता। बिम्सटेक में चीन ने जो खेल चुपचाप किया, उसकी झलक हमें 30-31 अगस्त 2018 की काठमांडो शिखर बैठक के बाद दिखी। काठमांडो बैठक के तुरंत बाद, 10 सितंबर 2018 को पुणे में बिम्सटेक देशों की सेना का काउंटर टेररिज्म के वास्ते साझा अभ्यास था। तब इसका नेपाली मीडिया में जमकर विरोध हुआ। ओली सरकार दबाव में थी। अंदरखाने पेइचिंग द्वारा आंखें तरेरने के बाद नेपाल ने ज्वाइंट मिल्ट्री एक्सरसाइज में आने से मना कर दिया। इससे भारत सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में बस इतना कहा कि 'आंतरिक दबाव' की वजह से साझा सैन्य अभ्यास में आने से मना कर रहे हैं, यह बात बहुत कंविसिंग नहीं है। बिम्सटेक के मंच पर चीन द्वारा शह-मात का यह पहला प्रहार था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अजीब-सा संयोग है कि 2019 में श्रीलंका में सार्क शिखर सम्मेलन होना है और इसी साल कोलंबो में बिम्सटेक की पांचवीं बैठक भी। पीएम मोदी के लिए बड़ा सवाल यह भी है कि वह इन दो में से किसके लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, दक्षेस या बिम्सटेक को?

ज्ञान गंगा

क्षमता

जग्गी वासुदेव

किसी भी मशीन में, चाहे जिस तरह के ईंधन का उपयोग हो रहा हो, उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से जलता है? उदाहरण के लिये एक सामान्य कार में आप जिस गैसोलीन का उपयोग करते हैं, वह रेसिंग कार या विमान के गैसोलीन से अलग होता है, और उसका कारण है ईंधन का आसानी से जलना! आपने पेट्रोल पम्पों पर अलग-अलग स्तर के ऑक्टेन वाले गैसोलीन देखे होंगे- 87, 89, 90, 91, 93, 96.. हम जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो 100 ऑक्टेन वाला तेल लेने के लिये तीन गुना रकम देते थे क्योंकि उससे अचानक ही हमारी मोटरसाइकिल ऐसे दौड़ती थी, जैसे दूसरी नहीं दौड़ सकती थी। सबसे ज्यादा आसानी से पचने वाला भोजन है-फल। पाचन का अर्थ है, जठराग्नि-पाचन अग्नियां। अगर इन अग्नियों को सबसे ज्यादा प्रभाव के साथ जलना है तो, निश्चित ही फल सबसे अच्छे हैं। दुर्भाग्यवश, बहुत सारे लोगों को आलस्य और जड़ता में ही मजा आता है। उनको जीवन ने छुआ ही नहीं है, तो उन्हें अपने एक भाग के मृत होने में ही मजा आता है। बस पड़े रहना, सोना, नशे में रहना और ज्यादा खाना, उन्हें सक्रिय, गतिशील और जीवंत रहने से बेहतर लगता है। ऐसे ही लोगों के लिये फल समस्या हो सकते हैं क्योंकि फल आप को जागृत और सतर्क रखते हैं। अगर ये पके हुए न हों तो ये आप को मदहोश नहीं रखेंगे। हां, उच्च स्तर की जागरूकता भी आप को अपार आनंद, गहरा सुख और नशा दे सकती है। मगर अब प्रश्न यह है कि क्या मैं फल खा कर भी सामान्य जीवन जी सकता हूं? एक सरल उत्तर, जो आप के जीवन की सामान्य क्रियाओं में ही है। मान लीजिये, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर बीमार हैं, तो कोई भी आप के लिये चिकन बिरयानी नहीं लाएगा। वे आप के लिये फल ही लाएंगे क्योंकि आप के रिश्तेदार, मित्र भी समझते हैं, ''तुम ये सब खा कर बीमार हो गए हो, कम से कम अब तो सही ढंग से खाओ'! आप जानते हैं, आदम ने भी शुरु आत फल से ही की थी। तो फल एक ऐसी चीज है जिसे प्रकृति ने भोजन के रूप में ही बनाया है। आम में गुठली महत्वपूर्ण भाग है, उसका गूदा और छिलका तो पशु, पक्षियों को आकर्षित करने के लिये है, जिससे वे फल खाएं और उसके बीज को कहीं दूर तक पहुंचा दें।

आज का राशिफल

मेष आर्थिक योजना सफल होगी। भाई या पड़ोसी का सहयोग रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। विरोधियों का पराभव होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

वृषभ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। विरोधियों का पराभव होगा। धन लाभ की संभावना है।

कर्क पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण के योग हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप होने की संभावना है। भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। पराक्रम में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। विरोधी परास्त होंगे।

तुला बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

वृश्चिक आर्थिक योजना सफल होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। धन हानि की संभावना है।

मकर राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। नए अनुबंधन प्राप्त होंगे।

कुम्भ संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी अभिन्न मित्र या रिश्तेदार से मिलाप होगा। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की पीड़ा मिल सकती है।

मीन व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के कारण तनाव हो सकता है। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। धन लाभ की संभावना है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

छोटी उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी

चर्चित चेहरा/ अरुण नैथानी

किस्मत कैसे करवट लेती है, इसकी जीवंत मिसाल है ओडिशा की चंद्राणी मुर्मू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद नौकरी के लिये तैयारी कर रही चंद्राणी के लिये अब नौकरी तलाशने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। वह अब नौकरी बांटने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रही है। वह सत्रहवीं लोकसभा के लिये ओडिशा के केन्द्रपार से सांसद बनी है। खास बात यह है कि वह सत्रहवीं लोकसभा में देश की सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई है। उसकी उम्र पच्चीस साल ग्यारह महीने है। पिछली लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद हरियाणा के दुष्यंत चौटाला थे, जिनकी उम्र चुनाव के वक्त छब्बीस साल थी। यह बात अलग है कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है, वहीं चंद्राणी के पिता के परिवार में सक्रिय राजनीति में हाल-फिलहाल कोई नहीं है। हां, कभी नाना जरूर सक्रिय राजनीति में रहे। आदिवासी समाज में उनका नाम सम्मान से लिया जाता रहा है। ओडिशा ने देश को कई तरह के संदेश चुपचाप बिना किसी शोर-शराबे के दिये हैं। चक्रवाती तूफान को चकमा देने वाले ओडिशा ने नवीन पटनायक को लगातार पांचवीं बार राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बार राज्य ने 33 फीसदी महिलाओं को संसद में भेजा, जबकि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में संसद में दशकों से लटका हुआ है। तीसरा यह कि राज्य ने सबसे कम उम्र की एक आदिवासी लड़की को संसद में भेजा है। यानी बड़े बदलाव बिना शोरगुल के भी होते हैं, ओडिशा इसका साक्षी बना है। निःसंदेह भुवनेश्वर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक पहुंचने का चंद्राणी का सफर एक परीकथा जैसा है। भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके नौकरी तलाश रही चंद्राणी की किस्मत अचानक ही बदल गई। उसके मामा ने पूछा कि क्या राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हो। उसने तुरंत हामी भर दी। दरअसल, पार्टी किसी पढ़ी-लिखी प्रत्याशी की तलाश में थी। बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक ने उसे टिकट दिया और वह जीत भी गई। चंद्राणी के पिता सरकारी नौकरी करते हैं। सामान्य परिवार की चंद्राणी के पास न घर है, न गाड़ी और कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, कुल रकम बीस हजार के आसपास। चंद्राणी का किसी भी कंपनी में कोई शेयर और बीमा पॉलिसी भी नहीं है। हां, माता-पिता द्वारा दिये गये सौ ग्राम के सोने के जेवर जरूर हैं। इसके बावजूद लोगों का इतना प्यार मिला कि सांसद बन गई। हां, उसके नाना हरिहर सोरेन सांसद रह चुके हैं। राजनीति में जो थोड़ी-बहुत दिलचस्पी रही, वह नाना के घर के राजनीतिक माहौल के चलते ही रही। आज भी लोग ओडिशा में कहते सुने जाते हैं कि अरे ये हरिहर सोरेन की नातिन है। चंद्राणी अपनी सफलता का सारा श्रेय नवीन पटनायक को देती है, जिनके प्रयासों से उसे सांसद बनने का मौका मिला। ओडिशा की केन्द्रपार सीट से जीती चंद्राणी ने इस चुनाव में राजनीति के अनुभवी भाजपा नेता व दो बार सांसद रह चुके अनंत नायक को हराया। आदिवासी बहुल इलाके में उनकी जीत का अंतर 66200 था। अब चंद्राणी मुर्मू अपने इलाके में शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहती है। उसका मानना है कि इस आदिवासी इलाके में सरकार की तमाम योजनाएं हैं, मगर शिक्षा के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। उन्हें अधिकारों व सुविधाओं के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है। कुल 21 सांसदों वाले राज्य में सात महिलाओं का चुना जाना नारी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक को छोड़कर शेष छह महिला सांसद ठीक-ठाक पढ़ी -लिखी भी हैं। इनमें

पांच महिला सांसद बीजू जनता दल से हैं और दो भारतीय जनता पार्टी से। बीजू जनता दल की सांसदों में प्रमिला बिसोयी, मंजूलता मंडल, राजश्री मलिक, शर्मिष्ठा सेठी शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई सांसदों में भुवनेश्वर से जीती अपराजिता सडांगी तथा बलंगिरी से जीती संगीता कुमारी सिंहदेव शामिल हैं। चंद्राणी अपने शैक्षिक अनुभवों से क्षेत्र के विकास को नयी दिशा देना चाहती हैं। उसका मानना है कि वह बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बजाय जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देगी। उसका लक्ष्य है कि क्षेत्र में युवाओं के रोजगार, महिलाओं और आदिवासियों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाये। उसका मानना है कि उनका क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, मगर इसके बावजूद बेरोजगारी नीतियों की विफलता को दर्शाती है। बहरहाल, चंद्राणी अपनी नई पारी को लेकर खासी उत्साहित है। वह कहती है कि मैंने पढ़ाई के दौरान कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में भविष्य तलाशूंगी। अब मौका मिला है तो कुछ नया करने का प्रयास रहेगा। संयुक्त परिवार में रहने वाली चंद्राणी के माता-पिता और दो बहनें उसकी सफलता से खासी प्रफुल्लित हैं।

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला बाजार गिरावट लेकर हुआ बंद

मुंबई।

घरेलू शेयर बाजार में आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सुबह कारोबार की शुरूआत बढ़त के साथ हरे निशान पर हुई और कारोबार की समाप्ति पर ये गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ है। गिरावट के इस माहौल में कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 117.77 अंक यानि 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 39,714.20 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पचास शेयरों वाले निफ्टी में भी कारोबार की समाप्ति पर गिरावट देखने को मिली और ये 23.10 अंक यानि 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,922.80 के स्तर पर बंद हुआ। गौरतलब है कि कल के कारोबार के दौरान शेयर बाजार सुबह बढ़त के साथ हरे निशान पर खुला और कारोबार की समाप्ति पर भी ये बढ़त के साथ ही हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार की शुरूआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 62.40 अंक यानि 0.16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 39,564.45 के स्तर पर खुला और कारोबार की समाप्ति पर ये 329.92 अंक यानि 0.84 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 39,831.97 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का पचास शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी कारोबार की शुरूआत में 12.15 अंक यानि 0.10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,873.25 के स्तर पर खुला और कारोबार की समाप्ति पर ये 84.80 अंक यानि 0.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,945.90 के स्तर पर बंद हुआ।

ईरान से तय सीमा से अधिक तेल आयात पर लगेगा प्रतिबंधः अमेरिका

वाशिंगटन:

अमेरिका ने आगाह किया है कि ईरान से तय सीमा से अधिक खरीदे गए कच्चे तेल को प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। यह बयान उन खबरों की पृष्ठभूमि में आया है कि भारत और चीन ईरान से तेल की खरीद के विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों को ईरान से तेल की खरीद से छूट देने से मना कर दिया था। ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाने की कोशिश के तहत उसने यह कदम उठाया है। इससे पहले भारत सरकार के एक अधिकारी के हवाले से यह खबर आ रही थी कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली, ईरान से तेल के आयात के रास्ते तलाश रहा है। इसके बाद अमेरिका ने अपनी स्थिति को फिर से दोहराया है। पिछले सप्ताह अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट समाप्त होने के बाद दो मई से भारत ने ईरान से तेल का आयात रोक दिया था। ईरान के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि और विदेश मंत्री के वरिष्ठ नीतिगत सलाहकार बायन हूक ने बृहस्पतिवार को कहा, अब तेल खरीद के लिए और छूट नहीं दी जाएगी। जिन देशों को इससे छूट दी गई थी, उनके लिए एक सीमा तय की गई थी। यह प्रतिबंधित सीमा नवंबर, 2018 से मई, 2019 तक के लिए थी। उन्होंने बताया कि नवंबर से मई के दौरान ईरान से तय सीमा से अधिक तेल आयात के किसी भी तरह के प्रयासों को प्रतिबंध के दायरे में लाया जाएगा।

नीरव मोदी ने जमानत के लिए ब्रिटेन के हाई कोर्ट में दायर की याचिका

लंदन:

लंदन की वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ा दिए जाने के बाद भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से उसकी जमानत याचिका तीन बार खारिज की जा चुकी है। नीरव मोदी पर पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नीरव मोदी धोखाधड़ी को अंजाम देकर ब्रिटेन भाग गया जहां उसे लंदन के एक बैंक में नया खाता खुलवाते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार नीरव का प्रत्यर्पण करवाने की फिराक में है। मामले में भारत सरकार का पक्ष रख रही क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीसी) ने बताया कि नीरव की जमानत याचिका पर ब्रिटिश हाई कोर्ट में 11 जून को सुनवाई होगी। इससे पहले, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जज एम्मा अर्बथनॉट ने नीरव मोदी को गुरुवार को 27 जून तक की हिरासत में भेज दिया। उसी दिन अदालत ने भारत सरकार को 14 दिनों के भीतर यह बताने को कहा था कि यदि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किया गया तो उसे किस जेल में रखा जाएगा। नीरव मोदी को केंद्रीय लंदन में स्थित मेट्रो बैंक की एक शाखा के प्रत्यर्पण वारंट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में ही है।

अमेरिका को अंदेशा, चीनी सरकार के साथ जानकारियां सांझा कर रही है हुआवे

नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार को अंदेशा है कि हुआवे चीन की सरकार के साथ अहम जानकारी साझा कर रही है, इसलिए वह इस दूरसंचार कंपनी का विरोध कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि हुआवे चीनी सरकार का ही एक माध्यम है। चीन के साथ व्यापार युद्ध को बढ़ाते हुए अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सुरक्षा चिंताओं के चलते हुआवे को काली सूची में डाल दिया है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को उसके दूरसंचार उपकरण उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में हुआवे के मामले को शामिल किए जाने की संभावना जताती थी। पोम्पिओ ने फॉक्स बिजनेस न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा हुआवे चीनी सरकार का ही माध्यम है और वे बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के हुआवे को वैश्विक स्तर पर रोकने से जुड़े प्रयासों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसे समझना अमेरिकियों के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां सरकार के साथ सहयोग करें और नियमों का पालन करें लेकिन कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका की निजी कंपनियों को निर्देश नहीं दे सकता जबकि चीन में यह बात बहुत अलग है।

अमेरिका को आर्थिक आतंकवाद का समर्थक बताया

वहीं अमेरिका के रवैये पर चीन ने अमेरिका पर जोरदार हमला बोलते हुए उस पर 'खुल्लम खुल्ला आर्थिक आतंकवाद' फैलाने का आरोप लगाया। दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच काफी समय से विवाद जारी रहे। व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अटकी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने चीन की वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री किसान योजना में बाकी किसानों का पंजीकरण होगा शुरू

नई दिल्ली: चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले छोटे और मझोले किसानों को प्रत्येक वर्ष तीन किस्तों में 6,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए प्रत्येक की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अब राज्य पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अपलोड करना शुरू करेंगे। हम अधिक लाभार्थियों तक तेजी से पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि डेटा में कई गड़बड़ियां थी और मंत्रालय ने बहुत से आवेदनों को दोबारा पुष्टि के लिए राज्यों को वापस भेजा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-बीजेपी सरकार वाले राज्यों ने अभी तक इस योजना में हिस्सा नहीं लिया है। अधिकारी का कहना था, इन तीन राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। किसान इस योजना को लागू नहीं करने के कारण राज्य सरकारों से नाराज दिखे हैं। कर्नाटक में भी मौजूदा सरकार को झटका लगा है। राजस्थान में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल एक सीट जीत सकी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार चला रही है। सरकार को इन राज्यों के जल्द योजना में शामिल होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा, हम इन राज्यों को लाभार्थियों की लिस्ट भेजने के लिए दोबारा कहेंगे। पहले भी हमने इन्हें योजना में शामिल होने के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की थी। 2015 की कृषि जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 12.6 करोड़ छोटे और हाशिए पर मौजूद किसान हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों तक करने का वादा किया था।

लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल, डीजल के दाम

नई दिल्ली । तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की। पेट्रोल फिर सात पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है जबकि डीजल के दाम 12 से 13 पैसे लीटर कम हो गए हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 71.73 रुपये, 73.79 रुपये, 77.34 रुपये और 74.46 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में नई कटौती के बाद क्रमशः 66.51 रुपये, 68.27 रुपये, 69.69 रुपये और 70.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में सात पैसे लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 12 पैसे प्रति लीटर जबकि मुंबई में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है।

उबर का ग्राहकों को तोहफा, पेट्रोल पंपों पर ईंधन में मिलेगी भारी छूट

नई दिल्ली = उबर ने गुरुवार को देश भर में आईओसीएल के पेट्रोल पंपों पर चालकों को पेट्रोल, डीजल व सीएनजी में छूट की पेशकश करते हुए सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस कार्यक्रम के लिए 12,000 से ज्यादा उबर के चालक साझेदार पहले से ही पंजीकृत हो चुके हैं। उबर इंडिया एवं साउथ एशिया के शहरों के प्रमुख प्रभजीत सिंह ने एक बयान में कहा, इस साझेदारी का लक्ष्य ईंधन की कीमत को कम करना और उबर एप का इस्तेमाल अपनी आजीविका के लिए करने वाले चालक साझेदारों की सहायता करना है। उबर ने भारत में अपनी सेवाएं अपनी उबरब्लैक सेवा के साथ 2013 में शुरू की थीं और अपनी प्रीमियम उबरएक्स सेवा की शुरुआत 2014 में की। उबर वर्तमान में देश के 31 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और इसका और अधिक क्षेत्रों में विस्तार का लक्ष्य है।

सोना 300 रुपए की छलांग लगाकर करीब दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, चांदी हुई 150 रुपए महंगी

नई दिल्ली।

वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी और खुदरा जेवराती मांग आने से समर्थन पाकर दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 300 रुपए की छलांग लगाकर करीब दो सप्ताह के उच्चतम स्तर 33,170 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान सिक्का निर्माताओं के उठाव में आई तेजी से चांदी भी 150 रुपए की बढ़त में 37,550 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लंदन का सोना हाजिर 7.20 डॉलर की बढ़त के साथ 1,295.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। अगस्त का अमेरिकी सोना वायदा भी 7.50 डॉलर की तेजी में 1,299.90 डॉलर प्रति औंस बोला गया।

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक मैक्सिको के सभी उत्पादों पर पांच प्रतिशत का टैरिफ लगाने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड की धमकी से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश में बढ़ गया है। ट्रंप की आर्थिक नीति को निवेशक जोखिम भरे निवेश के लिए खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावनाओं ने भी सोने को मजबूती दी है। हालांकि ,दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर की मजबूती के कारण पीली धातु की चमक सीमित रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी हाजिर भी 0.03 डॉलर की तेजी के साथ 14.55 डॉलर प्रति औंस के भाव बिकी। वैश्विक तेजी के बीच घरेलू जेवराती मांग आने से सोना स्टैंडर्ड 300 रुपए चमककर 17 मई के बाद के उच्चतम स्तर 33,170 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। सोना बिट्टर भी इतनी ही तेजी के साथ 33,000 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव बिका। आठ ग्राम वाली गिन्नी 26,500 रुपए पर टिकी रही। सिक्का निर्माताओं के उठाव में तेजी आने से चांदी हाजिर 150 रुपए की बढ़त लेकर 37,550 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। चांदी वायदा 295 रुपए चढ़कर 36,390 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। सिक्का लिवाली और बिकवाली भी 1,000-1,000 रुपए की तेजी में क्रमशः 80 हजार और 81 हजार रुपए प्रति सैकड़ा पर पहुंच गए।

हाईकोर्ट का आदेश, 67 मरीजों को 2 हफ्ते में 25-25 लाख रुपए दे जॉनसन एंड जॉनसन

नई दिल्ली:

हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को गुरुवार को निर्देश दिया है हिप इम्प्लांट करवाने वाले उन 67 मरीजों को 25-25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान किया जाए जिन्हें फिर से सर्जरी करवानी पड़ी थी। कोर्ट ने कहा है कि दावेदारों को दो हफ्ते में चेक दे दिए जाएं। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

मरीज किसी मंच पर केस हारे तो भी कंपनी हर्जाना वापस नहीं ले सकेगी

कोर्ट के निर्देश से पहले कंपनी ने खुद कहा था कि वह मरीजों का वेरिफिकेशन कर चुकी है और हर्जाने के तौर पर 25-25 लाख रुपए का भुगतान करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने विवाद की जांच नहीं की है। इसलिए अभी जो भुगतान किया जाएगा उससे मरीजों का और हर्जाना मांगने का अधिकार खत्म नहीं होगा। अगर कोई अन्य न्यायिक मंच 25 लाख रुपए से ज्यादा हर्जाने का फैसला देता है तो कंपनी को सिर्फ अतिरिक्त रकम देनी होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि प्रभावित मरीज किसी मंच के समक्ष अपना दावे में सफल नहीं रहते तो कंपनी स्वेच्छा से दिए जा रहे 25 लाख रुपए के रिफंड की हकदार नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की अपील पर सुनवाई कर रहा था। मंत्रालय ने कंपनी से कहा था कि सभी प्रभावित मरीजों को हर्जाना दिया जाए। मंत्रालय ने जॉनसन एंड जॉनसन के हिप इम्प्लांट विफल रहने की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हर्जाना देने के लिए कहा था।

जॉनसन एंड जॉनसन ने 2010 में हिप इम्प्लांट फेल होने की शिकायतों के बाद दुनियाभर के बाजारों से दोषपूर्ण हिप इम्प्लांट वापस मंगवाए थे। भारत में 2017 में सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित किया था।

289 ने की थी शिकायत

दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण उपकरण के मामले में 289 लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें से 67 लोगों की पहचान की गई। इसी मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) पहले ही कंपनी को 4 मरीजों को क्रमशः 65 लाख, 74 लाख, 1 करोड़ और 90.26 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मरीजों के दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद कंपनी को मुआवजा देने को कहा है।

हिंदुस्तान कॉपर का 1,200 करोड़ पूंजीगत व्यय का लक्ष्य

कोलकाता

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में परिचालन से 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी ने 1,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पूंजीगत व्यय कंपनी की क्षमता का विस्तार करने, बंद पड़े खदानों को दोबारा चालू करने और नए खदानों को पट्टे पर लेने के लिए किया जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संतोष शर्मा ने संवाददाताओं से यहां कहा, हमने 2019-20 में 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस साल पूंजीगत व्यय की हमारी प्रतिबद्धता 600 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, हालांकि हम मौजूदा खदानों की क्षमता का विस्तार करने, बंद खदानों को दोबारा चालू करने और नए खदान पट्टे पर लेने के लिए इस वित्त वर्ष के लिए 1,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करना चाहते हैं।

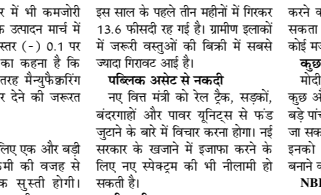

नई वित्त मंत्री निर्मला के सामने होंगी ये 10 बड़ी चुनौतियां

बिजनेस डेस्क:

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग और फिर रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण को अब वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में 18 अगस्त 1959 को जन्मीं सीतरमण ने मंत्री के रूप में अपने काम से सबको प्रभावित किया है लेकिन वित्त मंत्री के रूप में अब उनकी असली परीक्षा होगी। उन्हें ऐसे समय में यह जिम्मेदारी मिली है, जब अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि निर्मला को किन बड़ी मुश्किलों का सामना करना है।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती

देश की आर्थिक विकास दर पांच तिमाहियों के निचले स्तर 6.6त पर पहुंच गई है और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ग्रामीण खपत मांग में गिरावट और तेल की कीमतों में धीमी वृद्धि से हालत और बदतर हो सकती है। ऐसे में सीतरमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास रफ्तार को 7 फीसदी या इससे अधिक पर बनाए रखने की होगी।

तेल से खाद्य पदार्थों तक पर महंगाई की आंच

मोदी सरकार को 2014 से 2019 तक महंगाई के मोर्चे पर दिक्कत नहीं हुई। ईंधन और खाद्य पदार्थों के दाम कम रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनके दाम बढ़ने लगे हैं। पश्चिमी एशिया के तेजी से बदलते हालातों की वजह से तेल के दामों में आग लग सकती है तो हाल ही में जारी आंकड़े दिखाते हैं कि लंबे समय तक नरमी के बाद खाद्य पदार्थों के होलसेल दाम में वृद्धि हो रही है।

रोजगार का संकट

नए वित्त मंत्री को रोजगार के मोर्चे पर भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा। रोजगार के मुद्दे ने 2014 नरेंद्र मोदी को सत्ता दिलाई, लेकिन रोजगार संकट को लेकर विपक्ष लगातार उनपर हमलावर रहा। अब संभावित आर्थिक मंदी से रोजगार के नए अवसर पैदा करने में चुनौती और बढ़ जाएगी।

मैन्युफैक्चरिंग में कमी

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कमजोरी बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन मार्च में 21 महीने के निचले स्तर (-) 0.1 पर आ गया। जानकारों का कहना है कि भारत को चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर देने की जरूरत है।

डिमांड में सुस्ती

अगली सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती डिमांड में कमी की वजह से आने वाली आर्थिक सुस्ती होगी। एफएमसीजी से पैसेंजर वीइकल तक कंज्यूमर डिमांड में कमी से इकॉनमी को जोर का झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 के आखिरी तीन महीनों में एफएमसीजी सेक्टर की वृद्धि दर 16 फीसदी थी और इस साल के पहले तीन महीनों में गिरकर 13.6 फीसदी रह गई है। ग्रामीण इलाकों में जरूरी वस्तुओं की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

पब्लिक असेट से नकदी

नए वित्त मंत्री को रेल ट्रैक, सड़कों, बंदरगाहों और पावर यूनिट्स से फंड जुटाने के बारे में विचार करना होगा। नई सरकार के खजाने में इजाफा करने के लिए नए स्पेक्ट्रम की भी नीलामी हो सकती है।

जीएसटी 2.0

18 और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब से अब भी लोगों को दिक्कत है इसलिए इसको दो मुख्य स्लैब में मर्ज करने की जरूरत है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी जीएसटी को सरल करने की बात कही गई थी। हो सकता है सरकार इस बारे में कोई मजबूत कदम उठाए।

कुछ बड़े बैंकों का विकास

मोदी सरकार-2 के अंतर्गत कुछ और बैंकों का मर्जर करके बड़े पांच बैंकों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद सरकार इनको कैपिटल देकर मजबूत बनाने का काम कर सकती है।

NBFCs के लिए तरलता

NBFCs के कुछ असेट खरीदकर सरकार इन्हें बचाने का कदम उठाना होगा। इसे बॉन्ड से खरीदकर अन्य स्रोतों को विकसित करने पर ध्यान दिया जा सकता है।

किसानों का सशक्तीकरण

किसानों की आय को बढ़ाना मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में था। सरकार को किसान के लिए बाजार तैयार करने की जरूरत है जिससे वह अपने उत्पाद को आसानी से बेच सके। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं की भी जरूरत पड़ेगी।

स्टैम्प ड्युटी दस्तावेजों की पंजीकरण पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन हेतु जनसाधारण के विचार

सूरत। शुक्रवार को नायवब कलेक्टर सूरत स्टैम्प ड्युटी मुल्यांकन तंत्र के कार्यालय तथा दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के कार्यपद्धति कार्यालय व्यवस्था एवं सुविधा तकनीकी एवं कायदा नियम एवं तारीख ठराव में जन साधारण एवं सरकार दोनों के हित में वर्तमान समय के अनुरुप नीचे के मुद्दाओं अथवा उसके सिवाय यदि कोई मुद्दा हो तो उस सम्बन्ध में सुधारा वधारा से लगती सलाह एवं सूचना हेतु जन साधारण से अनुरोध है।

जिसमें :- 1. रजिस्ट्रेश एवं स्टैम्प एक्ट के तहत नियम व्यवस्था एवं जाहेर नामा ठराव (प्रस्ताव) परिपत्रों की सूचनाओं का अर्थघटन एवं कार्यान्वयन इस संदर्भ में अभी हाल के समय के संदर्भ एवं विधिक कार्यालय। ना. कोर्ट, ए.जी. कार्यालय द्वारा तथा अर्थघटन सम्बन्धित कायदा। नियमों की विसंगता अव्यावहारिक या विरोधाभासी, अस्पष्ट व्यवस्थाओं (व्याखाओ) के प्रति अवश्य ध्यान कषित करें।

2. हाल की पंजीकरण पद्धति कार्य पद्धति एवं मागें जाने वाले डाक्युमेन्टस आधार पुरावा/प्रमाण पत्र/विवारण एवं फार्म के नमूना के सन्दर्भ में।

3. अभी हाल की सब रजिस्ट्रार एवं नायब कलेक्टर (स्टैम्प ड्युटी) के कार्यालयों, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों की कार्यपद्धति एवं कुशलता, कार्यालय में जरुरी इन्फ्रास्टक्चर एवं तकनीकी व्यवस्था।

4. स्टैम्प ड्युटी की दर स्टैम्प पेपर विक्री एवं रिफण्ड।

5. हाल की मिल्कत की बाजार कीमत तप करने की पद्धति एवं उसकी विभिन्न कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन।

6. आपके विस्तार या कार्यालय में हाल की लोकेशन, ले-आउट, विल्डिंग के बदले सभी योग्य लोकेशन, ले आउट, विल्डिंग की सम्भावना, निश्चित स्थल व्यवस्था स्पष्ट रुप में दर्शाने हेतु।

7. हाल का पंजीकरण स्टैम्प ड्युटी, मूल्यांकन तंत्र की कार्यवाही में उपयोग में लेने योग्य उस उपलब्ध टोक्नोलोजी की संभावना।

8. हाल की पंजीकरण एवं स्टैम्प ड्युटी मूल्यांकन तंत्र की सब रजिस्ट्रार कार्यालय नायब कलेक्टर कार्यालय से शुरु कर के यहां के बड़े कार्यालय तक के मालखा (व्यवस्था) में परिवर्तन के संदर्भ में।

9. विभिन्न कार्यालयों में मांगी जाने वाली विगत, फार्म के नमूना की विगत एवं अन्य सम्बन्धित कागजात इत्यादि।

इस प्रकार राज्य के सुप्रिन्टेन्डेन्ट आफ स्टैम्प एवं इन्सपेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रतिपादित इस कपायत (कार्यवाही) स्वरुप जन साधारण एवं नागरिक सीधे पत्र द्वारा सुप्रि. आफ स्टैम्प एवं इन्सपेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन के कार्यालय स्टैम्प एवं पंजीयन (नोधणी) भवन, ख-5 सर्कल के पास सेक्टर 14 गांधीनगर सरकार की वेबसाइट या इमेल द्वारा अपनी सलाह एवं सुझाव भेज सकते है या फिर व्हाटस ऐप नं. 9879551751 पर भी ता. 6/6/2019 तक सुचनाये भेज सकते है।

पालनपुर में कामर्सियल काम्प्लेक्स में लिफ्ट खराब होने से तीन व्यक्ति फंसे

फायर ब्रिगेड ने रोयल प्लेटिनम विल्डिंग के प्रमुख को नोटिस

सूरत। शुक्रवार को पालनपुर पटिया केनाल रोड़ स्थित रोयल प्लेटिनम कमर्सियल काम्प्लेक्स में लिफ्ट की पहली मंजिल पर तीन व्यक्ति फंस गये थे। लिफ्ट खराब हो जाने से पिता पुत्री सहित अन्य एक युवती लगभग 30 मिनट जितना समय लिफ्ट में फंस गये थे।

फायर ब्रिगेड द्वारा सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। बाद में फायर ब्रिगेड द्वारा लिफ्ट को सील मार कर काम्प्लेक्स के प्रमुख को नेटिस भी दिया है। काम्प्लेक्स में चलता ट्यूसन क्लासीज की सूचना लेने हेतु पिता पुत्री गये थे। लिफ्ट में फंसे पिता पुत्री ने हेल्पलाइन नम्बर डायल करने पर काम्प्लेक्स को मैनेजमेन्ट दौडता हो गया। बाद में इस घटना के संदर्भ में स्थानीय कार्पोरेटर को सूचित किया गया। जिसमें सारा मामला बाहर आया था। चार दिन पहले भी इसी काम्प्लेक्स में ऐसी ही घटना बनी थी। जिससे फायर ब्रिगेड कोई दुर्घटना हो इसके पहले ही लिफ्ट सील कर कायदेसर कार्यवाही की है। जोकि लोगों की सुविधा हेतु लिफ्ट को रिपेयर करने के बाद खोली गयी थी।

शैक्षणिक संस्थाओं, कामर्शियल विल्डिंगों बाद इन्डस्ट्रियल विस्तारों में भी तोड़फोड़

सूरत। शुक्रवार को तक्षशिला आर्केड अग्निकाण्ड के बाद आग द्वारा 22 बालकों की मृत्यु हेतु जवाबदार डोम स्ट्रक्चर के अवैध बांधकाम को तोड़ने हेतु राज्य सरकार ने सूचना दी है। पालिका कमिश्नर की सूचना से आज सतत् छठे दिन विभिन्न जोन में 81 स्थलों पर 37 टीमों द्वारा गैरकायदे डोम स्ट्रक्चर की तोड़फोड़ चल रही है।

तक्षशिला अग्निकांड के आज बराबर एक सप्ताह का समय हुआ है। चौथे मंजिल के ट्यूशन एवं डिजाइनिंग कोचिंग क्लास में पढते 22 निर्दोष बालक आग में जल मरे और चौथी मंजिल से आग से बचने हेतु कूदने पर भी मृत्यु की भेंट चढ गये। इस दुर्घटना के बाद मनपा कमिश्नर द्वारा शहर की सभी ट्यूशन क्लासिज विद्यालोयं एवं संस्थाओं में ज्यादा लोग इकट्ठे होते है ऐसे में अगासी पर का डोम स्ट्रक्चर उतार गिराने की सूचना दी गयी है। आज विभिन्न 8 जोनों में 37 टीमों द्वारा 81 स्थलों पर अवैध बांधकामों को तोड़ा गया है। राज्देर जोन द्वारा आज 31 मई के दिन शाम तक अडाजण प्रसंग पार्टी प्लोट, खेतला आपा टी स्टाल, रोयल इनफील्ड जिम, जलाराम मसाला, आनन्द महल रोड़, महेरनगर में ट्यूशन क्लासिज, रणछोड़ नगर में टेम्पेरी स्टील तोड़ गिराने की कार्यवाही शुरु की है। साई स्केवेयर, प्रगति बहेरा मुंगा स्कूल, इन्टरवुड फर्नीचर टेस्टी रेस्टोरेन्ट की टेरिस का अवैध बांधकाम तोड़ गिराया है।

रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार को सरखेज रोजा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की।

विश्व व्यसन मुक्ति दिवस का अनोखा उत्सव शुक्रवार को मनाया गया। इसके तहत अहमदाबाद पुलिस और मेडिसिटी-सिविल अस्पताल के संयुक्त सान्निध्य में व्यसन मुक्ति अभियान के तहत एक रैली आयोजित की गई।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है

गुजरात में ४ दिनों में तापमान ४५ डिग्री तक जा सकता है

गुजरात में भीषण गर्मी, अहमदाबाद में ११४ लोग बेहोश होकर गिर पड़े : अहमदाबाद में आज का तापमान ४३.२

अहमदाबाद। गुजरात में गर्मी चरम पर है। अहमदाबाद सहित राज्य के १० शहरों में पारा ४४ के पार हो गया है। प्रशासन ने कई शहरों में यलो अलर्ट घोषित किया है। उधर, मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य में अगले चार दिनों में तापमान ४५ डिग्री तक जा सकता है। उत्तरीय अरब सागर में हाईप्रेशर के कारण तापमान में अचानक वृद्धि हुई है।

गर्मी के कारण अहमदाबाद शहर में करीब ११४ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं, गत तीन दिनों में ५०० से भी अधिक लोगों की तबियत खराब होने से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ये सभी लोग लू के शिकार हुए थे। अहमदाबाद शहर में गुरुवार को सीजन का सर्वाधिक तापमान ४४.३ रहा, वहीं राजधानी गांधीनगर में ४४.४ तापमान दर्ज किया गया।

राज्य में ४४.७ डिग्री तापमान के साथ कंडला एयरपोर्ट सर्वाधिक गर्म रहा। इस बीच आइएमडी गुजरात के निदेशक जयंत सरकार ने बताया कि अगले पांच दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात में गर्मी की कोई चेतावनी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य में दो दिनों के बाद तापमान में कमी आने की संभावना है। मॉनसून छह जून तक केरल पहुंच जाएगा और फिर धीरे-धीरे, यह उत्तर की ओर बढ़ेगा। गुजरात में मई के आखिरी दिनों में तापमान में अचानक वृद्धि होने के कारण सौराष्ट्र में अमरेली, सुरेंद्रनगर और कच्छ में तापमान ४४ डिग्री के पार हो गया। अगले तीन-चार दिन तक यही हालत रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अहमदाबाद शहर का अधिकतम तापमान २.६ डिग्री बढ़कर ४४.३ डिग्री तक पहुंच गया। इससे लोग दोपहर को घर के बाहर नहीं निकले। रास्ते सुनसान पड़े थे। अगले चार दिनों तक अहमदाबाद का तापमान ४४ से ४५ डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

हत्या के बाद शव को माधवनगर के निकट फेंका

सूदखोरों ने कॉन्ट्रैक्टर का अपहरण करके हत्या कर दी

मृतक राजस्थान के सिकर का निवासी : ४ के खिलाफ साणंद पुलिस स्टेशन में अपहरण-हत्या का अपराध दर्ज

अहमदाबाद, ३१ मई।

साणंद निकट स्थित माधवनगर गांव में रहते युवक का गत दिन रात को अपहरण करके हत्या किए जाने की घटना सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। ब्याज पर दिए गए पैसे की तकरार में सूदखोरों ने कॉन्ट्रैक्टर युवक का अपहरण करके हत्या कर दी इसके शव को माधवनगर बस स्टेंड के निकट फेंक कर फरार हो गये। साणंद पुलिस ने यह पूरे मामले में चार आरोपियों के विरूद्ध अपहरण और हत्या का अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। सूदखोरों ने मरने वाले युवक ने ब्याज पर लिए रुपये नहीं चुकाने पर इसका गाड़ी में अपहरण करके अज्ञात स्थल पर ले जाकर डंडे द्वारा पिटाई करके हत्या कर दी। इसके बाद माधवनगर बस स्टेंड के निकट फेंक कर फरार हो गये। इस घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में जानकारी सामने आई है कि, मूल राजस्थान का सीकर के उटडी गांव का निवासी और फिलहाल में अहमदाबाद विरमगाम हाइवे पर साणंद के निकट स्थित माधवनगर गांव में रहता सुमेरसिंह मीणा फलोरिंग टाइल्स का कॉन्ट्रैक्टर था। सुमेरसिंह ने साणंद के गोधावी गांव में रहते योगेश वाघेला नाम के युवक से ब्याज पर दो लाख रुपया लिया था। यह ब्याज चुकाने में देरी होने पर सूदखोर योगेश और इसके तीन दोस्तों ने मिलकर गत देर रात को सुमेरसिंह का कार में अपहरण कर लिया और अज्ञात जगह ले जाकर इसके साथ मारपीट करके हत्या कर दी। सुबह में शव को माधवनगर बस स्टेंड के निकट फेंक कर फरार हो गये। साणंद पुलिस ने अब पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खोज बीन शुरू कर दी है।

गुजरात : तापमान.....

अहमदाबाद, ३१ मई।

अहमदाबाद समेत कहां-कितना न्यूनतम तापमान रहा वह निम्न प्रकार है।

स्थल	न्यूनतम तापमान
अहमदाबाद	४३.२
डीसा	४१.२
गांधीनगर	४३.५
वीवी नगर	४२.१
वडोदरा	४२
सूरत	३४.२
वलसाड	-
अमरेली	-
भावनगर	३९.९
द्वारका	३३.१
ओखा	३३.९
पोरबंदर	३३.५
राजकोट	४३.७
वेरावल	३३.६
दीव	३४.६
सुरेन्द्रनगर	४४.८
महुवा	३३.८
भुज	३९.४
नलिया	३५.६
कंडला पोर्ट	३९.६
कंडला एयरपोर्ट	४०.८

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)